रक्षा बजट के बाद यूपी में बढ़ सकते हैं डिफेंस कॉरिडोर

मुख्यमंत्री ने आम बजट के यूपी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया
कहा- जरूरत पर डिफेंस कॉरिडोर के नोड की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आम बजट के यूपी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में रक्षा क्षेत्र में एक लाख करोड़ की भारी वृद्धि की गई है। उप्र डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। वे सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बजट की जानकारी दे रहे थे।

सीएम ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रदेश में छह नोड विकसित किए गए हैं, जिनके लिए अब तक लगभग 12 से 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। करीब 40,000 युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट, कानपुर में अडानी एम्युनेशन, झांसी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तथा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर डिफेंस कारिडोर के नोड की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

बायो-फार्मा सेक्टर की संभावनाएं हुई सुदृढ़ : सीएम ने कहा कि बजट से बायो-फार्मा सेक्टर में संभावनाएं बढ़ी हैं। ललितपुर में लगभग 1,200 एकड़ क्षेत्रफल में बल्क ड्रग पार्क विकसित हो रहा है जबकि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 700 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना प्रदेश के 1.05 लाख से अधिक राजस्व गांवों के ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि माघ मेले की सफलता ने प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को रखा है। देशभर की 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में दो स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, सारनाथ (वाराणसी) और हस्तिनापुर (मेरठ)। अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को भी इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बजट में 10,000 टूरिस्ट गाइडों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन स्थलों की रैंकिंग भी जारी की गई है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के कई पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जा रहा है।

200 शहरी निकायों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि आम बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 762 शहरी निकाय हैं, जिनमें से लगभग 200 अर्बन बॉडीज ऐसी हैं, जिनकी आबादी 5 लाख या उससे अधिक है। इनमें 17 नगर निगमों सहित कई नगर पालिकाएं शामिल हैं। हर जिले में इमरजेंसी व ट्रॉमा केयर सेंटर खोलने की व्यवस्था की गई है। यह पहल अनावश्यक मृत्यु दर को कम करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

खेल उद्योग में मेरठ के बाद आगरा व कानपुर

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में समर्थ योजना से खेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जबकि आगरा और कानपुर, लीडर क्लस्टर के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में पांच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने वाराणसी को प्रस्तावित किया है।

पीडीए केवल बहाना, असली लक्ष्य परिवारवाद

सीएम ने पीडीए के नाम पर किए जा रहे राजनीतिक हमलों पर कहा कि पीडीए केवल एक बहाना है, जबकि असली लक्ष्य परिवारवाद है। जो लोग आज पीडीए की बातें कर रहे हैं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे तब देश और प्रदेश के गरीब, युवा, किसान और वंचित वर्ग के आत्मसम्मान और आत्मगौरव की चिंता क्यों नहीं की गई। पहले भी गरीबी थी, समस्याएं थीं, लेकिन तब चर्चा केवल अपने परिवार की होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक परिवार मानकर गरीब, नौजवान, महिला और किसान के हित को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। यह बजट नए भारत के नए यूपी का प्रतिबिंब है।